हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 13 मार्च 2026, समय 1305 (5 मिनट)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत में हरियाणा की अग्रणी भूमिका रहेगी। इसके लिए हरियाणा निरंतर प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और गरीब उत्थान के चार स्तंभों पर काम करने का आह्वान किया है। हरियाणा सरकार इन सभी पर तेजी से कार्य कर रही है। आज हरियाणा का किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ प्राकृतिक खेती और बागवानी को अपना रहा है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। आज महिलाएं कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भरपूर योगदान दे रही हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए स्टार्टअप नीति बनाई है। गरीब उत्थान के लिए मजबूती से कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम जनधन खाता योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने फ्यूचर डिपार्टमेंट भी बनाया है। इसका मकसद, भविष्य के लिए लंबे समय को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाना है। इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को शोध के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि विश्वविद्यालयों के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में शोध कर सकें और यह पहचान सकें कि किन-किन क्षेत्रों में क्या समस्याएँ हैं। साथ-साथ उनका समाधान भी निकाल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत एआई, अनुसंधान और विकास को अपना रहा है। पंचकूला और गुरुग्राम को एआई हब बनाने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी आयोजित एआई सम्मेलन में इस क्षेत्र से जुड़े अनेक विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने भाग लिया। एआई हब के लिए अनेक कंपनियों ने रुचि दिखाते हुए प्रस्ताव भी दिए हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ना और उन्हें इस क्षेत्र में कुशल बनाना है, ताकि भविष्य में एआई के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में सरकार ने 10, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें से लगभग छह पर तेजी से काम शुरू हो चुका है, जबकि बाकी चार पर भी जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इन टाउनशिप का उद्देश्य उद्योगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां हरियाणा में निवेश कर सकें।

सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी औद्योगिक नीतियों को भी मजबूत किया है। नई औद्योगिक नीति और सेमीकंडक्टर नीति पर भी काम किया जा रहा है, ताकि हाई-टेक उद्योगों को हरियाणा में स्थापित होने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

महिला किसानों को सशक्त बनाने, किसान उत्पादक संगठनों -FPO को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन क्षमता बढ़ाने तथा जलवायु-अनुकूल आधार-संरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा कैथल और करनाल जिलों में कई महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास पहलों का शुभारंभ किया गया। नाबार्ड के अध्यक्ष, डॉ.

शाजी के.वी. ने इन पहलों का उद्घाटन करते हुए महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन, आजीविका विविधीकरण और हरियाणा में सतत ग्रामीण समृद्धि को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

कैथल जिले के फरल गांव में उन्होंने सरस धारा दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला रखी और विकसित एफ़पीओ की सरसों तेल प्रसंस्करण यूनिट एवं उसके बिक्री केंद का उद्घाटन किया। नाबार्ड ने गांव में एक ऋण संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें बैंकों, कार्यान्वयन एजेंसियों, एफ़पीओ प्रतिनिधियों और लाभार्थियों ने भाग लिया ताकि ग्रामीण उद्यमों के लिए ऋण संवितरण को मजबूत किया जा सके। नाबार्ड अध्यक्ष ने संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों तथा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत खरखोदा खंड में गठित जैविक एफ़पीओ एवं जींद किसान जन निर्माण एफ़पीओ को स्वीकृति पत्र और चेक भी सौंपे, ताकि आजीविका और कृषि-आधारित गतिविधियों के लिए ऋण संवितरण में वृद्धि हो सके। इस दौरान सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फरल में निर्मित वर्षा जल संचयन पुनर्भरण संरचना भी औपचारिक रूप से ग्राम वासियों को समर्पित किया गया।

करनाल जिले के मंगलोरा गांव में डॉ. शाजी ने महिलाओं द्वारा संचालित हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति एफ़पीओ की बिलोना घी निर्माण इकाई का उद्घाटन किया और महिला सदस्यों तथा लाभार्थियों से संवाद किया।

डॉ. शाजी ने बताया कि नाबार्ड ने पिछले एक दशक में महिला किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने और करीब 13,000 महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, नाबार्ड ने पुनर्वित्त एवं प्रत्यक्ष वित्त के रूप में हरियाणा में कुल ₹30,050 करोड़ की ऋण सहायता वितरित की है।